<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इरेडा के सीएमडी ने ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 में समावेशी, हरित विकास के लिए संतुलित मार्गों पर प्रकाश डाला



पुरी, ओडिशा, 7 दिसंबर 2025

आज पुरी में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट में, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने ओडिशा के स्वच्छ-ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने और भारत के स्थिरता एजेंडे को आगे बढ़ाने में इरेडा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

"ग्रीन एंड क्लीन: बैलेंसिंग इकोलॉजी एंड इकोनॉमी" पर पैनल में बोलते हुए, इरेडा के सीएमडी ने इस बात पर जोर दिया कि आरई विकास, डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा परिवर्तन के भारत के दृष्टिकोण से, जिम्मेदारी केवल देश के नेताओं या कॉर्पोरेट नेतृत्व पर निर्भर नहीं हो सकती है। हर स्तर पर नेताओं- राज्यों, जिलों, पंचायतों, गांवों और यहां तक कि परिवारों के भीतर भी नेट जीरो हासिल करने की जिम्मेदारी को सामूहिक रूप से निभाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे केवल एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है जो नवीकरणीय-ऊर्जा विकास और पारिस्थितिक संतुलन दोनों का समर्थन करने वाले एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाता है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के सबसे बड़े शुद्ध हरित ऋणदाता इरेडा ने मजबूत संचालन प्रणाली, डिजिटल पेपरलेस प्रक्रियाओं और उद्योग-अग्रणी परिसंपत्ति-गुणवत्ता द्वारा समर्थित देश भर में 2.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है और 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन वैश्विक और घरेलू जलवायु-वित्त निवेशकों से पर्याप्त रुचि को आकर्षित कर रहा है।

चक्रीय आर्थिक प्रथाओं, कार्बन बाजारों, जैव विविधता ऑफसेट और जलवायु वित्त के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए, श्री दास ने कहा कि ये उपकरण अब सतत और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। ओडिशा, एक प्रमुख इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादक, धातुओं की रीसाइक्लिंग और हरित हाइड्रोजन एकीकरण सहित चक्रीय विनिर्माण को अपनाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे निर्यात के लिए प्रीमियम ग्रीन स्टील का उत्पादन संभव हो सके और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिले।

उन्होंने पूरे ओडिशा में एक ग्रीन हाइड्रोजन हाईवे की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जो घोषित ग्रीन अमोनिया क्षमता के 7 एमटीपीए से अधिक और कई औद्योगिक समूहों द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट और रासायनिक इकाइयों के साथ हाइड्रोजन उत्पादन का सह-पता लगाने से महत्वपूर्ण औद्योगिक दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को खोला जा सकता है।



कार्बन बाजारों पर, उन्होंने कहा कि ओडिशा के व्यापक वन और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र उन्नत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) और डिजिटल कार्बन रजिस्ट्रियों के माध्यम से जलवायु-वित्त जुटाने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

इरेडा की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, श्री दास ने कहा कि एजेंसी पहले ही ओडिशा में 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है, जिसमें हाइड्रो, सौर, इथेनॉल और विनिर्माण में लगभग 1,800 करोड़ रुपये की ऋण पुस्तिका है। उन्होंने कहा कि इरेडा अपनी गिफ्ट सिटी की सहायक कंपनी के माध्यम से साझा हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे, प्लग-एंड-प्ले आरई पार्कों, वितरित सौर और विदेशी मुद्रा ऋणों को वित्तपोषित करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, "चक्रीयता, जलवायु वित्त और प्रकृति-सकारात्मक विकास को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, इरेडा भविष्य के लिए टिकाऊ, समुदाय-केंद्रित विकास प्रदान करने के लिए ओडिशा के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। "



इस कार्यक्रम में ओडिशा के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव और ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव (ऊर्जा) श्री विशाल कुमार देव के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, डेवलपर्स, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

श्री दास के साथ, पैनल चर्चा में सुश्री लीना बैकर, पूर्व प्रवर्तन निदेशक, स्वीडन सरकार और द रॉयल फाउंडेशन फॉर पीस ग्लोबल फंड की अध्यक्ष शामिल थीं; प्रो. माधवी श्रीनिवासन, कार्यकारी निदेशक, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर; और डॉ. ध्रुबा पुरकायस्थ, सलाहकार (जलवायु और ऊर्जा), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया।

टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज और आईआईटी कानपुर के सहयोग से ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन 5-7 दिसंबर तक आयोजित किया गया था।